बुधवार 25 मई 2022

आप की क्रांति

www.aapkikranti.com | @aapkikrantinews

दिल्ली में तीन जगहों पर नए चार्जिंग, स्वैपिंग स्टेशन बनेंगे

नई दिल्ली. आप की क्रांति। दिल्ली के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को चार्जिंग में दिक्कत न आए इसके लिए राजधानी में तीन स्थानों पर चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। जैन ने बुधवार को यहाँ बताया कि केजरीवाल सरकार दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत किया जा रहा है। ई-व्हीकल की बैटरी खत्म होने पर उसे री-चार्ज करने में वक्त की बबार्दी ना हो, साथ ही रिचार्ज प्रक्रिया आसान हो, इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से पटपड़गंज, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर-5 और नरेला सेक्टर-बी में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ई-व्हीकल की डिस्चार्ज बैटरी को बदलकर पूरी तरह चार्ज बैटरी लगाने की व्यवस्था को आसान बनाना है।

खत्म हो रही कांग्रेस!

चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले तीसरे नेता बने कपिल सिब्बल

नई दिल्ली. आप की क्रांति। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ दी है और इस तरह से वह इस साल कांग्रेस छोड़ने वाले पांचवें बड़े नेता हैं। सिब्बल ने बुधवार को खुद कांग्रेस छोडने की जानकारी देते हुए बताया कि वह कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर के एक दिन बाद 16 मई को पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से नामांकन कर रहे हैं।

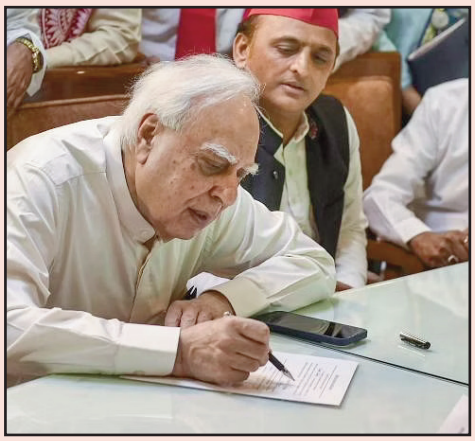

बढ़ती मुद्रास्फीति की मार

विजय प्रकाश श्रीवास्तव

मुद्रास्फीति एक तरफ लोगों की क्रयशक्ति तो कम कर ही देती है, लोग निवेश करने से भी बचते हैं। इस तरह मांग में कमी होती जाती है और उत्पादन भी घटता चला जाता है। जब निवेश नहीं होता तो विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है और इस प्रकार एक दुश्चक्र बनता जाता है, जिससे निकलना कठिन होता जाता है। भारत का मध्यवर्ग अपनी बचत को आमतौर पर बैंकों या डाकघर में मियादी जमा (एफडी) के रूप में रखना पसंद करता है, क्योंकि यहां उसे अपनी रकम सुरक्षित लगती है और इसमें बचत खाते की तुलना में ब्याज भी ज्यादा मिलता है। मियादी जमा की अवधि पूरी होने पर ब्याज स्वरूप जो भी रकम मिलती है, उसे पाकर यह वर्ग खुश हो लेता है लेकिन कम ही लोग यह समझ पाते हैं कि ब्याज को मिला कर उन्हें अपनी जो रकम बैंक या डाकघर से मिली है, उसका वास्तविक मूल्य कई बार उस राशि से कम होता है जो उन्होंने जमा की थी। यदि किसी को उसकी जमाराशि

पर पांच फीसद का वार्षिक ब्याज मिलता है और मुद्रास्फीति की सालाना दर साढ़े छह फीसद है तो ब्याज कमाने के बावजूद मौद्रिक रूप से वह नुकसान में है। यानी ऊंची मुद्रास्फीति का क्या असर होता है, इसका यह एक सरल उदाहरण है। मुद्रास्फीति का व्यापक अर्थ महंगाई दर से है। इस महीने भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को चार फीसद से बढ़ा कर 4.40 फीसद कर दिया। इस वृद्धि का स्वागत कम और आलोचना ज्यादा हुई। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक ने यह कदम मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के एक उपाय के रूप में उठाया है। कुछ अर्थशास्त्री इसे मौद्रिक सख्ती के जरिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की रिजर्व बैंक की प्रतिबद्धता के रूप में भी देख रहे हैं। सरकार सबसे अधिक चिंतित खाद्य मुद्रास्फीति को लेकर है जिससे जन असंतोष बढ़ता है। कृषि उत्पादों से जुड़ी मुद्रास्फीति के इस साल अप्रैल के जो आंकड़े आए हैं, उन्हें लेकर रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय भी कम परेशान नहीं हैं। मई 2014 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 8.3 फीसद दर्ज की गई थी। इस साल अप्रैल में यह 7.8 फीसद रही। मुद्रास्फीति की यह दर रिजर्व बैंक के निर्धारित छह फीसद की सहन योग्य दर से काफी ज्यादा है। हाल में मौद्रिक नीति की घोषणा के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा भी था कि उनकी प्राथमिकताओं के क्रम में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, विकास से पहले है। हालांकि इस दृष्टिकोण से कई अर्थशास्त्री सहमत नहीं हैं। इनका कहना है कि सरकार का काम विकास सुनिश्चित करना और मुद्रास्फीति को दायरे में रखना दोनों है। ऐसे में जब यहां दो लक्ष्य हैं तो इन्हें हासिल करने के लिए रणनीतियां भी दो होनी चाहिए। मुद्रास्फीति से निबटने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में तालमेल बेहद जरूरी है। **साभार: जनसत्ता**